

No.2/2/2004-Estt.(Pay-II)  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Personnel & Training

10 JUN 2005

New Delhi, Dated 1st June, 2005

**OFFICE MEMORANDUM**

Subject : Review of policy of NBR to officers appointed under Central Staffing Scheme.

.....  
The undersigned is directed to refer to O.M.No.2/13/93-Estt.(PayII) dated 26.10.93 on the above mentioned subject.

1. In Para 3 of the said O.M., the following conditions are prescribed:

(i) Proforma promotion is approved by the appropriate authority from a specific date;

(ii) All seniors (excluding those considered unfit) have started drawing pay of the higher post on or before the date from which the proforma promotion is granted;

(iii) The junior next below the officer should have also started drawing pay of the higher post from that date and his appointment thereto not being fortuitous; and

(iv) The benefit should be allowed on 'one for one' basis.

3. Instances have been brought to the notice of this Department where the officer who is outside his cadre and has been given proforma promotion under NBR in his parent cadre is not allowed to draw pay in the higher pay scale of the post to which he has been promoted proforma, because his senior or junior has not joined the post and has not started drawing pay in the higher pay scale. In order that the officer who has been granted pro-forma promotion does not suffer on this account, it has been decided to substitute the conditions (ii) and (iii) contained in O.M.No. 2/13/93-Estt.(Pay.II) dated 26.10.93 as under :

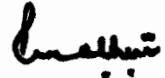
(ii) all seniors (excluding those considered unfit) should have been promoted on regular basis in that scale on or before the date from which the proforma promotion is granted.

(iii) the junior next below the officer should also have been promoted on regular basis to the higher post from that date and his appointment thereto not being fortuitous.

All other conditions prescribed in the O.M.No.2/13/93-Estt.(PayII) dated 26.10.93 shall remain unchanged.

4. This issues with the approval of Ministry of Finance vide their I.D.No. 7(10)-E-III(A)/2004 dated 27.12.2004.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders are being issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.



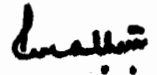
(Rita Mathur)

Deputy Secretary to the Government of India

To  
All Ministries/Departments of the Government of India.

Copies also forwarded to:

1. The Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control (with 400 spare copies)
2. Controller General of Accounts/Controller of Accounts, Ministry of Finance.
3. Secretaries to Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
4. Department of Personnel & Training (AIS Division)/JCA/Admn. Section.
5. Additional Secretary (Union Territories), Ministry of Home Affairs.
6. All State Governments and Union Territories.
7. Secretary, National Council (Staff Side), 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
8. All Members of the Staff Side of the National Council (JCM)/Departmental Council.
9. All Officers/Sections of the Department of Personnel & Training/Department of Administrative Reforms & Public Grievances/Department of Pension & Pensioner's Welfare.
10. Ministry of Finance, Department of Expenditure.
11. 300 spare copies.



( Rita Mathur )

Deputy Secretary to the Government of India.

**संख्या-2/2/2004-स्था.(वेतन-II)**

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक: 1 जून, 2005

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले अधिकारियों के संबंध में ठीक नीचे के नियम से सम्बद्ध नीति की समीक्षा ।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26.10.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/13/93-स्था.(वेतन-II) का हवाला देने का निदेश हुआ है ।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा-3 में निम्नलिखित शर्तें निहित हैं :-

- (i) प्रोफार्मा पदोन्नति समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट तारीख से अनुमोदित की जाए;
- (ii) सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने (अयोग्य घोषित किए जाने वालों को छोड़कर ) प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाने वाली तारीख को अथवा उससे पहले उच्च पद पर वेतन लेना आरम्भ कर दिया हो;
- (iii) उससे ठीक निचले अधिकारी द्वारा भी उस तारीख से उच्च पद का वेतन लेना आरम्भ कर दिया गया हो तथा उसकी नियुक्ति कोई आकस्मिक घटनावश नहीं हुई हो; तथा
- (iv) यह लाभ 'एक पर एक' आधार पर प्रदान किया जाए ।

3. इस विभाग के ध्यान में ऐसे उदाहरण लाए गए हैं जहाँ मूल संवर्ग से बाहर ऐसा कोई अधिकारी जिसे ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत अपने मूल संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति मिली हो उसे उसके प्रोफार्मा पदोन्नति वाले उच्च पद पर इसलिए वेतन नहीं दिया जा रहा होता क्योंकि उसके वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ अधिकारी द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया और उन्होंने उच्च वेतनमान में वेतन लेना आरम्भ नहीं किया । प्रोफार्मा पदोन्नति मिलने वाले अधिकारी को इस कारण कोई हानि नहीं पहुँचे इसलिए दिनांक 26.10.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/13/93-स्था.(वेतन-II) में विहित शर्तों (ii) तथा (iii) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाए :

- (ii) सभी वरिष्ठ अधिकारियों (अयोग्य घोषित किए जाने वालों को छोड़कर) को उस वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान किए जाने वाली तारीख से अथवा उससे पहले नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाए ।
- (iii) उससे ठीक निचले अधिकारी को भी उस तारीख से उच्च पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाए तथा उसकी पदोन्नति कोई आकस्मिक घटनावश न की गई हो । दिनांक 26.10.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-2/13/93-स्था.(वेतन-II) की बाकी सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

4. इसे वित्त मंत्रालय की दिनांक 27.12.04 की आई.डी. संख्या-7(10)-ई-III(क)/2004 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

5. भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जा रहे हैं ।

**रीता माथुर**  
(रीता माथुर)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।